उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail :infodirector.uk@gmail.com
Website :www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–07(09/184)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय हमारे लिये चिर स्थायी संसाधन हैं। सेवा हमारे स्वभाव में है। दक्ष मानव संसाधन की हमारे पास उपलब्धता है। हमारे युवा परिश्रमी, मेहनती व शिक्षित हैं। हमारे युवाओं को जरूरत व्यवसायिकता को अपनाने की है। जिसे उन्हें अपने स्वभाव से जोड़ना होगा, तभी वे पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संवाहक बन सकेंगे।

शनिवार को राजपुर रोड स्थित एक स्थानीय होटल में आयोजित सस्टेनेबल हिमालयन टूरिज्म सम्मान समारोह का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का एक मजबूत आधार बने इसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। 13 जिले 13 नये पर्यटन गंतव्यों की योजना इसी आधार पर बनायी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेल, सड़क व हवाई सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि शीघ्र ही चारधाम सड़क व ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना धरातल पर दिखाई देगी। हमारा प्रयास उत्तराखण्ड में अधिक से अधिक आउटडोर पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके लिये आवागमन के संसाधनों का विकास किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हैली सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के सुदूरवर्ती सीमान्त क्षेत्रों के नैसर्गिक सौन्दर्य को देखने देश व दुनिया के पर्यटक आ सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिये किये गये प्रयासों के भी सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। पर्यटन के क्षेत्र में कई निवेशक राज्य के प्रति आकर्षित हुए है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड अधिकांश राज्यों से सीधा जुड़ा है। देवबंद–रूड़की रेल लाईन व सहारनपुर–बागवत–दिल्ली हाईवे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली की दूरी और समय कम हो जायेगा। राज्य में विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ा है। राज्य में हाम–स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिये घरेलू दर पर बिजली व पानी की उपलब्धता के साथ ही इज–आफ–डूईंग बिजनेस के तहत नीतिगत परिवर्तन करते हुए इसके लैंड यूज के नियमों में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों के लिये उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स का भी आभार जताया। इस क्षेत्र के विकास हेतु प्राप्त होने वाले सुझावों पर अमल करने की भी बात उन्होंने कही। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने परिसर में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लगाये स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया।

कार्यक्रम में नेपाल सरकार के प्रतिनिधि श्री हेमराज बिष्ट, पर्यटन विभाग भारत सरकार के प्रतिनिधि मेजर योगेन्द्र यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर पीएचडी के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कालरा, श्री अनिल तनेजा सहित अन्य पर्यटन व्यवसायी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से वन एवं पर्यावरण से संबंधित राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

केन्द्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर ने वन क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत विस्तार एवं डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के विकास से संबंधित प्रस्तावों को संबंधित संरक्षित क्षेत्र की संस्तुति के साथ प्रेषित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सितम्बर में इसरो द्वारा सभी नदियों की मैपिंग की जायेगी। इससे नदी के सतह पर जमा खनिज की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त होने के साथ ही उसके वैज्ञानिक दोहन के लिये पारदर्शी प्रक्रिया व आधुनिक तकनीक युक्त उपकरण के माध्यम से निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इससे राज्य को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक हेक्टेयर तक के वन भूमि के प्रस्तावों की मंजूरी के लिये रीजनल आफिस अब डिसीजन आफिस के रूप में कार्य करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर ने यह भी आश्वासन दिया कि डिग्रेटेड फॉरेस्ट में राज्य की योजनाओं के लिये भी क्षति पूर्ति वृक्षारोपण की अनुमति दी जायेगी। अभी तक इसमें केन्द्र की योजनाओं के लिये ही व्यवस्था रही है। 1000 मीटर तक के ऊंचाई पर ग्रीन पातन की छटाई के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का भी केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने केम्पा के अधीन उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिये 30 सितम्बर के बाद भी व्यय की अनुमति प्रदान करने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग का कार्य पुनः शुरू किया गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि राजधानी देहरादून से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने के पश्चात् शहर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, जिसके बाद शहर एक नये रूप में नजर आयेगा। उन्होंने कहा कि शहर की लगभग 98 प्रतिशत जनता का यह मत है कि शहर से अवैध अतिक्रमणों को शीघ्र ही हटाया जाए, जिससे की आम जनमानस को ट्रैफिक जाम जैसी अन्य परेशानियों से निजात मिल सके। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने के लिये अग्रसर है, इसलिये आम जनमानस को स्मार्ट सिटी जैसे शहरों से अपेक्षा रहती है कि इसमें बुनियादी सुविधाओं का विकास हो। उन्होंने कहा कि शहर में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। स्कूली बच्चों को अभिभावकों द्वारा स्कूल छोडने व लेने के वक्त यातायात का दबाव अधिक बना रहता है, जिससे की इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फॉयर ब्रिगेड आदि को जाम में फसना पड़ता है। अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के बाद ऐसी कठिनाईयों से निजात मिल सकेगी।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि डाट काली मंदिर के पास टनल निर्माण हो जाने व मोहकमपुर फ्लाईओवर के बन जाने के बाद इन स्थानों पर लगने वाले लम्बे समय के ट्रैफिक जामों से आम जन मानस को निजात मिली है साथ ही उनका बेसकीमती समय भी बच रहा है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि शहर से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के कार्यों में अतिक्रमण हटाओं टास्क फोर्स को अपना सहयोग प्रदान करें।

आज दिनांक 07 सितम्बर, 2019 को इस अभियान के अन्तर्गत 09 अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण व 597 अतिक्रमणों का Reverification of Demarcation व 09 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को जनपद पिथौरागढ व चमोली के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर भारी वर्षा से हुए नुकसान की स्थिति के संबंध में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हरसंभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से जनहानि पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेजी से करने व प्रभावितों को आर्थिक सहायता के साथ ही अन्य राहत तुरंत उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(09/180)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को हरबर्टपुर क्रिश्चियन हास्पिटल के आई.पी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल की स्मृतियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेहमन अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध यह अस्पताल काफी लम्बे समय से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस अस्पताल में उत्तराखण्ड से ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व अन्य राज्यों से भी मरीज यहां ईलाज के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लेहमन अस्पताल के आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। पिछले वर्षों में राज्य में डॉक्टरों की सख्या 1087 से बढ़कर 2100 से अधिक हो गई है। राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 05 लाख रूपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 70 हजार से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। राज्य में 47 अस्पतालों में टेलीमेडिसिन व टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर अधिक फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती की गई है।

विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि लेहमन अस्पताल ने दुर्गम क्षेत्रों के अलावा गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपातकालीन स्थिति व आपदा जैसी परिस्थितियों में अस्पताल प्रशासन का सराहनीय सहयोग रहा है।

इस अवसर पर विधायक श्री जार्ज आईवान ग्रेगरी मैन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ई.एच.ए. डॉ. सुनील गोकावी, हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल मैनेजिंग डयरेक्टर डॉ. मैथ्यू सेमुअल आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देश के पहले हेलीकाप्टर सम्मेलन का देहरादून में हुआ आयोजन

- **''हेलीकाप्टर के माध्यम से कनेक्टीवीटी में विस्तार'' थीम पर आधारित था सम्मेलन।**
- **नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार व फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन।**
- **मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में हर साल, सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की।**
- **उड़ान योजना में चिन्हित स्थानों के लिए हेली सेवाएं देने पर राज्य सरकार, भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी देगी।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में हेली सेवाओं के विस्तार की बहुत सम्भावनाएं हैं। उत्तराखण्ड में प्रति वर्ष, हेलीकाप्टर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उड़ान योजना में चिन्हित स्थानों के लिए हेली सेवाएं देने पर राज्य सरकार, भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री, सहस्त्रधारा हेली ड्रोम में आयोजित हेलीकाप्टर समिट 2019 के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे।

हेलीकाप्टर समिट 2019, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार व फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस तरह का हेलीकाप्टर समिट, भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम ''हेलीकाप्टर के माध्यम से कनेक्टीवीटी में विस्तार'' थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां हेली सेवाएं बहुत जरूरी हैं। सीमांत क्षेत्रों तक सड़क मार्ग से जाने में 20 घंटे तक लग जाते हैं जबकि हेलीकाप्टर से मात्र 1:30 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों की प्राकृतिक सुदंरता का कोई मुकाबला नहीं है। उत्तराखण्ड में धार्मिक पर्यटन के साथ ही खर्चीले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। हमारे प्रयासों से पिछले कुछ समय में फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखण्ड पंसदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के समय मुम्बई में फिल्मकारों के साथ बैठक की गई थी। फिल्म निर्माता श्री महेश भट्ट पहले रोमानिया में अपनी फिल्म की शूटिंग करना चाहते थे। हमने उन्हें उत्तराखण्ड आमंत्रित किया। वे यहां आए और बहुत से दूरस्थ क्षेत्रों तक घूम कर आए। वे यहां की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। आतिथ्य उत्तराखण्ड के स्वभाव में है। देश–विदेश से बहुत से लोग, उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों तक जाना चाहते हैं। परंतु उनके पास समय की कमी होती है। इसलिए यहां हेली सेवाओं की बहुत जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड दैवीय आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रभावितों को बचाने व राहत पहुंचाने में हेली सेवाएं बहुत ही उपयोगी हैं। हम राज्य में हेली एम्बुलेंस की सेवा देना चाहते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में गम्भीर रूप से बीमार लोगों को हायर सेंटर कम समय में पहुंचाने के लिए भी हेली एम्बुलेंस जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वर्ष में औसतन 2 लाख लोग हेली सेवाएं ले रहे हैं। हमारे यहां 51 हेलीपेड, 2 एयरपोर्ट व 1 एयरस्ट्रिप है। इसी प्रकार टिहरी में एक वाटर ड्रोम विकसित कर रहे हैं।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केदारनाथ आपदा व हाल ही में आराकोट आपदा में बचाव व रहत के काम में हेली सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि राज्य के छोटे–छोटे स्थानों को कनेक्टीवीटी देने के लिए हेलीसेवा को बढ़ावा देना होगा। उत्तराखण्ड पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि करने वाले अग्रणी राज्यों में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकटता, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, औद्योगिक वातावरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, जलवायु, स्वच्छ वातावरण, उच्च स्तरीय स्कूल, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, एमआरओ सुविधाओं की उपलब्धता बहुत से ऐसे कारक हैं, जिनसे हेली विनिर्माता कम्पनियां उत्तराखण्ड आ सकती हैं।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला ने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला साधन हेलीकाप्टर हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में एयरपोर्ट की बजाय हेलीपोर्ट विकसित किए जा सकते हैं। यदि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार हेलीपोर्ट विकसित कर सकती है।

श्री खरोला ने कहा कि भारत में पहली बार हेलीकाप्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे अद्वितीय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री व राज्य सरकार को बधाई दी। गत पांच वर्षों से सिविल एवियेशन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में भारतीय आसमान में 600 से ज्यादा विमान उड़ रहे हैं। हेलीकाप्टर

सेवाओं में भी काफी सम्भावनाएं हैं। मुख्यतः चार बातों पर फोकस करना होगा। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में हेली सेवाएं बढ़ाने के लिए नियमों में क्या संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरा, एटीएफ टैक्स आदि में छूट सहित अन्य किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। उड़ान योजना में एटीएफ टैक्स केवल 1 प्रतिशत है। तीसरा, सुरक्षा प्रबंधन और चौथा इन्फ्रास्ट्रक्चर।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक डा. संजीव चोपड़ा ने कहा कि हेली सेवाओं को एफोर्डेबल बनाने की चुनौति है। उन्होंने बताया कि अकादमी में तीन हेलीपेड पर व्यावसायिक सेवाएं प्रारम्भ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव सुश्री उषा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में हेली कनेक्टीवीटी के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता है। टिहरी झील में सी–प्लेन संचालित करने के लिए वाटर ड्रोम विकसित किया जा रहा है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मेयर श्री सुनील उनियाल गामा व फिक्की की सिविल एवियेशन समिति के अध्यक्ष श्री आनंद स्टेनले ने भी सम्बोधित किया। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने अतिथियों का स्वागत किया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ये पुरस्कार 06 सितम्बर 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किए गए। उत्तराखंड की ओर से सम्मानित होने वाले प्रतिनिधियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सचिव पेयजल, श्री अरविन्द सिंह हयांकी के नेतृत्व में आए सभी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि इसी मनोयोग से कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सभी को स्वच्छता अभियान में सहयोग करना होगा। कोई भी अभियान जन सहभागिता से ही पूरा हो सकता है। स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत की कल्पना साकार की जा सकती है। उत्तराखंड में गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इन नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने की पहली जिम्मेदारी भी उत्तराखंड की है। गंगा और यमुना की स्वच्छता के साथ ही स्वच्छ उत्तराखंड के लिए हम सब को दृढ़ संकल्प होकर अपना योगदान देना जरूरी है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार पुरस्कार दिये गये :–

श्रेष्ठ राज्य	– उत्तराखण्ड
श्रेष्ठ जनपद	– उत्तरकाशी
स्वच्छ आईकॉनिक स्थल (तृतीय चरण)	– ग्राम माणा, जनपद चमोली।
श्रेष्ठ नामामि गंगे ग्राम	– अजीतपुर, जनपद हरिद्वार
श्रेष्ठ गंगा ग्राम	– उत्तरकाशी के ग्राम–बगोरी
महिला चैम्पियन श्रेणी(राष्ट्रीय स्तर)	– श्रीमती गीता मौर्या, अध्यक्ष, शक्ति स्वयं सहायता समूह, सहसपुर देहरादून
स्वच्छ भारत समर इन्टरशीप	– श्री चन्द्र प्रकाश, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल

इस अवसर पर डीएम उत्तरकाशी आशीष चौहान, परियोजना निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्री उदयराज सिंह, तत्कालीन प्रधान बगोरी भवान सिंह राणा व प्रधान अजीतपुर श्री मायाराम उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग